भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1841

उत्तर देने की तारीख -11/12/2025

विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह क्षेत्रों में सेवाप्रदाय प्रणाली को सुदृढ़ करना

†1841. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

श्रीमती कमलेश जांगड़े:

श्रीमती हिमाद्री सिंह:

श्री दिलीप शइकीया:

श्री विद्युत बरन महतो:

श्री भोजराज नाग:

श्री काली चरण सिंह:

श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:

डॉ. राजेश मिश्रा:

डॉ. मन्ना लाल रावत:

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

डॉ. हेमांग जोशी:

श्री दिनेशभाई मकवाणा:

श्री नलिन सोरेन:

श्री नव चरण माझी:

श्री आलोक शर्मा:

श्री महेश कश्यप:

श्री जुगल किशोर:

श्री बलभद्र माझी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)**:** सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत देश में विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह (पीवीटीजी) क्षेत्रों में सेवाप्रदाय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए दुमका, झारखंड और जम्मू-कश्मीर सहित राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं और शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख): देश में विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह (पीवीटीजी) क्षेत्रों में पीएम-जनमन के अंतर्गत कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों की उक्त क्षेत्रों/राज्यों सहित क्षेत्रों/राज्यों राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग): विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह (पीवीटीजी) क्षेत्रों में पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित सेवाओं की प्रभावी सेवाप्रदाय सुनिश्चित करने के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ): उक्त योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ): क्या सरकार का झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित देश में पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत उक्त केन्द्रों के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों के शीघ्र निर्माण/मानव संसाधन की उपलब्धता/स्थायी भवनों की स्थापना हेतु कोई विशेष योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च): पीवीटीजी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सेवा को सुदृढ़ करने, नियमित पोषण आपूर्ति सुनिश्चित करने, मातृ/शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने/मोबाइल आंगनवाड़ी/मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करने के लिए राज्य-वार और जिला-वार की गईं/प्रस्तावित विशेष पहलें क्या हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने दुमका जिले, झारखंड और सहित 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी चिन्हित पीवीटीजी नहीं हैं। दुमका ज़िला, झारखंड और शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अनूपपुर, कटनी, शहडोल और उमरिया जिलों में पीएम जनमन के तहत शुरू से दिए गए लाभों का ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया हैं।

(ख): पीएम जनमन के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति **अनुलग्नक II** में दी गई है।

(ग), (ङ) और (च): महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, छह सेवाएं जैसे पूरक पोषण (एसएनपी), प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और इन्हें स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के ज़रिए प्रदान किया जाता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसमें विभिन्न घटकों को लागू करने की ज़िम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित छत्रप (अम्ब्रेला) योजना है, जहाँ किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकृत करने और सेवा प्राप्त करने के लिए कोई प्रवेश प्रतिबंध नहीं है। यह मिशन पीवीटीजी इलाकों सहित पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

पीएम जनमन के तहत झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के पालघर जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति **अनुलग्नक III** में दी गई है।

पीएम जनमन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति **अनुलग्नक IV** में दी गई है।

(घ): राज्य सरकार द्वारा आवास स्तर के डेटा संग्रह कार्य द्वारा एकत्रित किए गए डेटा के आधार पर, सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत, शहडोल, सीधी और सिंगरौली पीवीटीजी की आबादी लगभग 2 लाख होने का अनुमान है। अभियान के तहत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की वास्तविक संख्या, अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अधीन है।

अनुलग्नक I

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा, श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री दिलीप शड़कीया, श्री विद्युत बरन महतो, श्री भोजराज नाग, श्री काली चरण सिंह, श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी, डॉ. राजेश मिश्रा, डॉ. मन्ना लाल रावत, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, डॉ. हेमांग जोशी, श्री दिनेशभाई मकवाणा, श्री नलिन सोरेन, श्री नव चरण माझी, श्री आलोक शर्मा, श्री महेश कश्यप, श्री जुगल किशोर तथा श्री बलभद्र माझी द्वारा "विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह क्षेत्रों में सेवाप्रदाय प्रणाली को सुदृढ़ करना" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †1841 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

(i) दुमका ज़िला, झारखंड में पीएम जनमन के तहत शुरू से दिए गए लाभों प्रदत्त लाभों का विवरण (31.10.2025 की स्थिति के अनुसार)

मंत्रालय का नाम	जिले का नाम	दुमका
ग्रामीण विकास मंत्रालय (मकान)	मकान स्वीकृत	4392
	पूरे हुए मकान	563
ग्रामीण विकास मंत्रालय (सड़क)	स्वीकृत सड़कें (किमी में)	40.650
	पूरी हुई सड़कें (किमी में)	1
जल शक्ति मंत्रालय	स्वीकृत गांवों की संख्या	433
	संतृप्त गांवों की संख्या	123
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वीकृत एमएमयू	10
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या (संख्या)	5
	काम शुरू हुआ (संख्या)	1
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत एडब्ल्यूसी की संख्या	35
	संचालित एडब्ल्यूसी की संख्या	34
दूरसंचार विभाग	कवरेज के लिए स्वीकृत पीवीटीजी बस्तियों की संख्या	54
	कवर की गई पीवीटीजी बस्तियों की संख्या	50
विद्युत मंत्रालय	आवास को मंजूरी दी गई	523
	आवास विद्युतीकृत	512

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत आवास	41
	आवास विद्युतीकृत	41
जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	9
	कार्य शुरू करने वाले वीडीवीके की संख्या	9
	स्वीकृत एमपीसी की संख्या	4
	पूरे किए गए एमपीसी की संख्या	-

(ii) शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत अनूपपुर, कटनी, शहडोल और उमरिया जिलों में पीएम जनमन के तहत प्रदत्त लाभों का विवरण (31.10.2025 की स्थिति के अनुसार)

मंत्रालय का नाम	राज्य का नाम	मध्य प्रदेश			
	जिले का नाम	अनूपपुर	कटनी	शहडोल	उमरिया
ग्रामीण विकास मंत्रालय (मकान)	मकान स्वीकृत	3886	115	19086	15602
	पूरे हुए मकान	3350	114	13865	9050
ग्रामीण विकास मंत्रालय (सड़क)	स्वीकृत सड़कें (किमी में)	213.850	3.5	84.780	64.17
	पूरी हुई सड़कें (किमी में)	22	-	30	3
जल शक्ति मंत्रालय	स्वीकृत गांवों की संख्या	195	11	427	288
	संतृप्त गांवों की संख्या	91	4	239	124
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वीकृत एमएमयू	3	1	10	1
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या (संख्या)	4	-	6	6
	काम शुरू हुआ (संख्या)	2	-	2	0
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत एडब्ल्यूसी की संख्या	26	1	66	50
	संचालित एडब्ल्यूसी की संख्या	23	1	66	49

दूरसंचार विभाग	कवरेज के लिए स्वीकृत पीवीटीजी बस्तियों की संख्या	42	-	22	14
	कवर की गई पीवीटीजी बस्तियों की संख्या	11	-	7	4
विद्युत मंत्रालय	आवास को मंजूरी दी गई	1366	57	1736	699
	आवास विद्युतीकृत	1128	57	1228	699
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत आवास	236	-	508	-
	आवास विद्युतीकृत	-	-	150	-
जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	8	-	26	-
	कार्य शुरू करने वाले वीडीवीके की संख्या	-	-	26	-
	स्वीकृत एमपीसी की संख्या	9	1	11	11
	पूरे किए गए एमपीसी की संख्या	1	1	1	3

अनुलग्नक II

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा, श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री दिलीप शइकीया, श्री विद्युत बरन महतो, श्री भोजराज नाग, श्री काली चरण सिंह, श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी, डॉ. राजेश मिश्रा, डॉ. मन्ना लाल रावत, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, डॉ. हेमांग जोशी, श्री दिनेशभाई मकवाणा, श्री नलिन सोरेन, श्री नव चरण माझी, श्री आलोक शर्मा, श्री महेश कश्यप, श्री जुगल किशोर तथा श्री बलभद्र माझी द्वारा "विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह क्षेत्रों में सेवाप्रदाय प्रणाली को सुदृढ़ करना" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †1841 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पीएम जनमन के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**स्वीकृत एडब्ल्यूसी (संख्या)**	**संचालित एडब्ल्यूसी (संख्या)**
1	आंध्र प्रदेश	192	73
2	बिहार	59	58
3	छत्तीसगढ़	191	191
4	गुजरात	67	67
5	झारखंड	495	410
6	कर्नाटक	23	23
7	केरल	7	7
8	मध्य प्रदेश	704	628
9	महाराष्ट्र	178	178
10	मणिपुर	75	25
11	ओडिशा	89	89
12	राजस्थान	51	51
13	तमिलनाडु	55	55
14	तेलंगाना	85	80
15	त्रिपुरा	221	221
16	उत्तर प्रदेश	1	1
17	उत्तराखंड	7	6
	कुल	**2500**	**2163**

अनुलग्नक III

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा, श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री दिलीप शइकीया, श्री विद्युत बरन महतो, श्री भोजराज नाग, श्री काली चरण सिंह, श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी, डॉ. राजेश मिश्रा, डॉ. मन्ना लाल रावत, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, डॉ. हेमांग जोशी, श्री दिनेशभाई मकवाणा, श्री नलिन सोरेन, श्री नव चरण माझी, श्री आलोक शर्मा, श्री महेश कश्यप, श्री जुगल किशोर तथा श्री बलभद्र माझी द्वारा "विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह क्षेत्रों में सेवाप्रदाय प्रणाली को सुदृढ़ करना" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1841 के भाग (ग), (ङ) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पीएम जनमन के तहत झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के पालघर ज़िला में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / राज्य	ज़िला	स्वीकृत एडब्ल्यूसी (संख्या)	संचालित एडब्ल्यूसी (संख्या)
चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड	चतरा	20	20
	लातेहार	5	5
	पलामू	42	38
महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़	धमतरी	19	19
	गरियाबंद	9	9
	महासमुंद	1	1
महाराष्ट्र	पालघर	14	14

अनुलग्नक IV

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा, श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री दिलीप शइकीया, श्री विद्युत बरन महतो, श्री भोजराज नाग, श्री काली चरण सिंह, श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी, डॉ. राजेश मिश्रा, डॉ. मन्ना लाल रावत, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, डॉ. हेमांग जोशी, श्री दिनेशभाई मकवाणा, श्री नलिन सोरेन, श्री नव चरण माझी, श्री आलोक शर्मा, श्री महेश कश्यप, श्री जुगल किशोर तथा श्री बलभद्र माझी द्वारा "विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह क्षेत्रों में सेवाप्रदाय प्रणाली को सुदृढ़ करना" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1841 के भाग (ग), (ङ) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पीएम जनमन के तहत मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों (एमएमयू) की स्थिति

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**स्वीकृत और संचालित एमएमयू (संख्या)**
1	आंध्र प्रदेश	141
2	छत्तीसगढ़	58
3	गुजरात	17
4	झारखंड	55
5	कर्नाटक	5
6	केरल	24
7	मध्य प्रदेश	74
8	महाराष्ट्र	84
9	ओडिशा	50
10	राजस्थान	6
11	तमिलनाडु	105
12	तेलंगाना	29
13	त्रिपुरा	6
14	उत्तर प्रदेश	2
15	उत्तराखंड	24
16	पश्चिम बंगाल	14
कुल		**694**

*****